दैनिक जागरण

विनम्रता सभी गुणों की आधारशिला है

न्यायाधीशों की नियुक्ति

न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में मतभेद की खबरें एक बार फिर सतह पर हैं। इस पर हैरानी नहीं। ऐसे मतभेद पहले भी सामने आएं हैं और यह तय है कि आगे भी तब तक आते रहेंगे जब तक वह कोलेजियम व्यवस्था बनी रहती है जिसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने झारखंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में प्रोन्नत करने की जो सिफारिश की थी उस पर सरकार ने नए सिरे से विचार करने को कहा, लेकिन उसके पास वही नाम फिर से भेज दिए गए। अब सरकार के पास इन नामों को मंजूर करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या यह विचित्र नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के पास अधिकार के नाम पर मात्र यह करने को है कि वह कोलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को हरी झंडी दे दे? यह तो मुहर भर लगाने वाला काम हुआ। निःसंदेह यह कहना कठिन है कि कोलेजियम की ताजा सिफारिश पर सरकार की आपत्ति कितनी उचित थी, लेकिन यह ठीक नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करें और इस क्रम में पारदर्शिता के लिए कहीं कोई स्थान भी नजर न आए। क्या कोई इसकी अनदेखी कर सकता है कि कुछ समय पहले खुद कोलेजियम ने उन न्यायाधीशों के नाम प्रोन्नति सूची से बाहर कर दिए थे जिन्हें खुद उसने ही तय किए थे? चूंकि इस मामले में न्यायाधीशों की वरिष्ठता की भी अनदेखी की गई थी इसलिए बार कौंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भी सवाल खड़े किए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। क्या इससे न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ी?

निश्चित तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक ऐसी प्रक्रिया जारी रहे जिसका संविधान में उल्लेख ही नहीं। यह उल्लेखनीय है कि दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा ही है। क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के बारे में यह कहा जा सकता है कि इन देशों की न्यायपालिका भारत से कम स्वतंत्र है? चिंताजनक केवल यह नहीं है कि वह कोलेजियम व्यवस्था बनी हुई है जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण माना था, बल्कि यह भी है कि इस व्यवस्था के दोष दूर करने का काम नहीं हुआ। कोलेजियम व्यवस्था के दोष दूर करने की बात न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी कानून को निरस्त करते वक्त कही गई थी। इस कानून को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह गैर संवैधानिक है, लेकिन यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर कोलेजियम की व्यवस्था संविधान के अनुरूप कैसे है? यह कोलेजियम व्यवस्था का ही परिणाम है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद के आरोप उछलते रहते हैं। एक ऐसे समय जब समूची न्यायपालिका में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ करना है तब यह देखना दयनीय है कि वह जजों की नियुक्ति के मसले को ही सुलझा पाने में नाकाम है।

चारधाम के दर्शन

उत्तराखंड में एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अब तक गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और शुक्रवार को बदरीनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। शुरुआती चरण में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जो जोश नजर आ रहा है वह बेहद सकारात्मक है। बेहद विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से शासन-प्रशासन ने यात्रा शुरू कराई है, उस पर उनकी पीठ थपथपाई जा सकती है। हालांकि, यात्रा की चुनौतियों व तैयारियों की असल परीक्षा तब होगी जब यात्रा अपने चरम पर होगी। अभी शुरुआती व्यवस्थाएं संतोषजनक कही जा सकती हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पहले से चौड़ा हुआ है। यात्रा को देखते हुए फिलहाल कटान का काम रोक दिया गया है। सड़कों पर पैराफिट लगाए जा रहे हैं और टूटे हुए मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ के जवान जगह-जगह तैनात किए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर जगह-जगह स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। आपात स्थिति के लिए हेली एंबुलेंस सेवा का प्रावधान किया गया है। एक और राहत देने वाली बात यह भी है कि चारधाम में हवाई सेवा के संबंध में दायर याचिका निरस्त हो चुकी है और सरकार ने यहां हेली सेवाओं के संचालन को टेंडर प्रक्रिया शुरू करा दी है। अगले कुछ दिनों में यहां हेली सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। जिस मौसम और बर्फबारी ने यात्रा को लेकर शासन-प्रशासन की पेशानी पर बल डाले हुए थे, अब वही यात्रियों के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहा है। मैदान में झुलसती गर्मी के बीच यात्रा पर आने वाले यात्रियों को पहाड़ों का खुशगवार मौसम मोहित कर रहा है। केदारनाथ व यमुनोत्री मार्ग पर हिमखंड पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। इन हिमखंडों के मई अंत तक रहने की संभावना है। कहा जा सकता है कि यात्रा की शुरुआत काफी बेहतर हुई है। सरकार भी इससे उत्साहित है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रा के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वे पूरे सीजन में बरकरार रहेगी।

जनतंत्र में सेंध लगाते अलोकतांत्रिक मूल्य

बद्रीनारायण

कहने को भारतीय जनतंत्र गहरा हो रहा है, किंतु दूसरी तरफ यह भारतीय जनगण के एक हिस्से को अपने में समाहित होने के दरवाजे भी बंद करता जा रहा है

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को एक महापर्व माना गया है। इस महापर्व का प्रमुख तत्व है मतदाताओं को वोट देने के लिए बूथ तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना। बूथ तक जाने का उत्साह ही चुनाव की उत्सवधर्मिता का परिचायक बनता है। पिछले कई चुनाव से वोटिंग के प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। अब अनेक चुनाव क्षेत्रों में करीब 60 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान हो रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। यह राजनीतिक जागरूकता राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले प्रचार, रैलियों, लोगों को एकजुट कर बूथ तक ले जाने के प्रयासों के कारण बढ़ रही है। इसके अलावा अनेक सामाजिक आंदोलनों और सिविल सोसायटी समूहों द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किए जाने वाले आंदोलनों के कारण भी मतदाताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त अनेक सांस्कृतिक-राजनीतिक समूहों यथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मददगार हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक फॉर्म प्रथम बार मत देने वाले मतदाताओं से भरवाया है। सिनेमा से जुड़े चर्चित लोगों ने भी मतदाताओं में वोट देने के प्रति लगाव, आकर्षण एवं प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शाहरुख खान द्वारा बनाया गया एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक सहित तमाम सोशल साइट्स पर मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, तृणमूल नेता ममता बनर्जी, राकांपा प्रमुख शरद पवार जैसे नेता भी लगातार मतदाताओं से मतदान के दिन बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं।

लोगों में बढ़ रही शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, जनतंत्र के प्रति लगाव आदि ने मिलकर भारत में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ाया है, लेकिन अगर उत्तर-पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर यह मत प्रतिशत 60 प्रतिशत के आसपास आकर थम सा गया दिखता है। इसका मतलब है कि अभी भी मतदाताओं का करीब 35-40 प्रतिशत भाग मतदान करने बूथ तक नहीं पहुंच रहा है। अगर चुनाव प्रचार के तरीकों का अध्ययन करें तो जाहिर होता है कि चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीके यथा होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर, लाउडस्पीकर के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर प्रचार करना एवं गाजे-बाजे के साथ जुलूस, प्रभात फेरी निकालना इत्यादि लगभग न के बराबर हो गया है। अब चुनाव प्रचार टीवी चैनलों, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स एवं मोबाइल संदेशों तक सिमट कर रह गया है। इस सबके बीच नेताओं की बड़ी रैलियां अभी भी चुनाव प्रचार के एक महत्वपूर्ण तरीकों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। बड़े चुनावों में रैलियों की तुलना में नुक्कड़ सभाएं कम हो रही हैं। नेतागण हेलीकॉप्टर के द्वारा देश को नापने में लगे हैं। ट्रेन, जीप, बस जैसे पारंपरिक संसाधनों से प्रचार, जिससे जनता के साथ संपर्क बने, भी लगभग खत्म हो गया है। एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का यह महापर्व समाज के एक खास वर्ग तक सीमित होकर रह गया है। समाज का शहरी, ग्रामीण, मध्यवर्ग, शिक्षित और वह तबका जिसके पास टेलीविजन, स्मार्टफोन इत्यादि रखने की क्षमता है वही आज चुनाव विमर्श की परिधि में है। शेष लोग चुनावी विमर्श की परिधि से बाहर ही हैं।

अवधेश राजपूत

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में घूमते हुए हमें अहसास हुआ कि इन जगहों पर न तो चुनावी विमर्श पहुंचे हैं, न ही चुनावी संवाद। कइयों को यह भी पता नहीं है कि इस क्षेत्र में किस दल से कौन-कौन चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में प्रत्याशियों की खामियों, खूबियों की कौन कहे, उनमें से कइयों के नाम भी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। न कहीं कोई चुनावी नारा दिखता है, न ही कोई पोस्टर। उपेक्षित समूहों के लोग प्रायः चुप हैं। अधिकांश लोगों को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के बारे में भी जानकारी नहीं है। चुनाव के वक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित समूहों में जनतंत्र के प्रसार का माध्यम धीरे-धीरे सीमित होता जा रहा है। जब तक दूरस्थ के सामाजिक समुदाय आभासी दुनिया से जुड़ने की शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक वे चुनावी विमर्श से भी दूर रहेंगे।

चुनावों को हम महापर्व कहते हैं, परंतु इसमें जो उत्सवधर्मिता पहले निहित थी वह अब कम होती जा रही है। पहले गांवों में बैलगाड़ी पर सामूहिक रूप से गीत गाती स्त्रियां सुबह-सुबह वोट देने जा रही होती थीं। चुनाव के दिन सचमुच उत्सव का माहौल होता था, किंतु धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति का लोप होता गया है। इस पर गौर करें कि एक तरफ लोक उत्सवधर्मिता के तत्व चुनाव से गायब होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इसे महापर्व कह रहे हैं। यह चिंता की बात है कि उपेक्षित समूहों की इसमें सहभागिता भी कम होती जा रही है। जनतंत्र एक अर्थ में जागरूक जनता की लोकशाही पर टिकी जन व्यवस्था है। जनतंत्र राजनीतिक रूप से गैर जागरूक जनता को अपने विकास की प्रक्रिया में शिक्षित भी करता चलता है। जनतंत्र अगर मात्र शिक्षित, जागरूक एवं राजनीतिक रूप से क्षमतावान सामाजिक समूहों का ही तंत्र होकर रह जाएगा तो उसके गहरे होने एवं प्रसारित होने की प्रक्रिया बाधित होगी। जनतंत्र जनता को राजनीतिक एवं जनतांत्रिक मूल्य सिखाने की पाठशाला भी है। आदर्श जनतंत्र में सार्थक वाद-विवाद एवं संवाद के माध्यम से जन नेतृत्व का चयन होता है। जाति, धर्म एवं निजी हितों, धनशक्ति आदि का सहारा लेकर जनमत को प्रभावित करना एक प्रकार से जनतंत्र में भी गैर जनतांत्रिक मूल्यों को चोर दरवाजे से प्रवेश कराना है।

कहने को भारतीय जनतंत्र गहरा हो रहा है, किंतु दूसरी ओर यह भारतीय जनगण के एक हिस्से को अपने में समाहित होने के दरवाजे भी बंद करता जा रहा है। यदि आपमें आज की जनतांत्रिक राजनीति में प्रवेश कर पाने की शक्ति नहीं है तो आपका अर्थात आपके सामाजिक समूह को इस जनतंत्र में कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं अगर जनतंत्र महज राजनीतिक रूप से जागरूक समूहों का ही लोक बनकर रह जाएगा तो गैर जागरूक नागरिकों-मतदाताओं को कौन पूछेगा? जाहिर है कि जनतंत्र राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा प्रणाली के रूप में तब हमारे समक्ष असफल हो जाएगा। जनतांत्रिक मूल्यों को सीखते हुए ही हम जनतंत्र को शक्तिवान बना सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता के लिए हमें जनतंत्र के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी होंगी। निर्बल, निरीह, मूक-सबका इसमें प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। जनता की मुख्यधारा के अतिरिक्त जनतंत्र में उपेक्षित सामाजिक धाराओं को बढ़ावा देना होगा। तब जाकर भारतीय जनतंत्र सतत रूप से विकासमान बना रह सकता है। नहीं तो वह जड़ एवं अवरुद्ध होकर सड़ांध पैदा करने लगेगा।

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं)

response@jagran.com

चुनाव नतीजों की तस्वीर

सुधीर पंवार

भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व बढ़ना तय है

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम चरणों तक आते-आते यह स्पष्ट हो रहा है कि आगामी लोकसभा का स्वरूप पिछली लोकसभा से भिन्न रहने वाला है। चुनावी सर्वेक्षणों एवं भविष्यवाणियों से इतर इसके स्पष्ट संकेत मौजूदा चुनावों की पृष्ठभूमि, सत्तापक्ष एवं विपक्ष के चुनावी मुद्दे, क्षेत्रीय दलो के परस्पर एवं राष्ट्रीय दलों के चुनाव पूर्व हुए गठबंधनों एवं महत्वपूर्ण नेताओं के साक्षात्कारों/बयानों से मिल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव दस साल की मनमोहन सिंह सरकार के सत्ता जनित विरोध, सरकार के कार्यकलापों पर सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुए कथित भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोजगारी पर युवाओं में बढ़ते असंतोष की पृष्ठभूमि में हुए थे। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के विरोध में हुए लोकपाल से जुड़े अराजनीतिक आंदोलन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के विरुद्ध जनमानस में गहरी छाप छोड़ी थी। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों के बीच लहराते तिरंगों ने पहली बार भ्रष्टाचार विरोध को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा था। मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध उपजे जनाक्रोश की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने अंतर्निहित हिंदुत्व छवि, गुजरात विकास मॉडल एवं युवा आकांक्षाओं के सफल संयोजन से न केवल केंद्र में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाया, वरन भाजपा को चुनाव जीतने वाली मशीन के रूप में स्थापित करने मे भी सफल रहे। कांग्रेस मात्र 44 सांसदों तक सीमित रह गई और अधिकांश क्षेत्रीय दल या तो भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में शामिल हो गए या फिर हाशिए पर सिमट गए।

मोदी सरकार के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भाजपा के 'अच्छे दिनों' के सपने से जनता का मोहभंग होने लगा तथा भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के नारों के बीच जनता ने भाजपा को उसके मजबूत गढ़ माने जाने वाले राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में हराकर कांग्रेस की सरकार बनवाई। देश के अधिकांश राज्यों में हुए लोकसभा उपचुनावों में भाजपा की हार ने उसके अविजित रहने के मिथक को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, फूलपुर एवं कैराना में हुए लोकसभा उपचुनावों के परिणामों में भाजपा को मिली चुनावी पराजय ने सपा-बसपा-रालोद गठबंधन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सफलताओं/असफलताओं के साथ-साथ भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की कार्यप्रणाली भी है। मोदी सरकार के तीन बड़े फैसले-नोटबंदी, जीएसटी एवं किसानों की दोगुनी आमदनी मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लाने में नाकाम रहे हैं। सरकारी नौकरियों एवं रोजगार के घटते अवसरों ने आकांक्षी युवाओं का भाजपा से मोहभंग ही किया है। भाजपा की राज्य

सरकारें भी कार्यसंस्कृति में सुधार लाने में असफल रही हैं। इसका प्रभाव भी लोकसभा चुनावों पर हुआ। राम मंदिर, धारा 370 एवं समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार के रवैये ने भाजपा एवं संघ के पुराने कार्यकर्ताओं एवं परंपरागत समर्थकों को यदि असंतुष्ट नहीं तो निराश अवश्य किया है।

चुनावों के ठीक पहले सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन, पिछड़ों के आरक्षण को विभाजित करने की घोषणा एवं संघ के आनुषंगिक संगठनों द्वारा उग्र हिंदुत्व पर दिए गए बयानों एवं कार्रवाइयों ने दलितों, पिछड़ों एवं मुस्लिमों को सशंकित और भाजपा के विरोध में संगठित किया है। इन चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी विफलता अखिल भारतीय विस्तार के बाद भी राष्ट्रीय विमर्श का अभाव है जिसका प्रमाण भाजपा नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों में अलग-अलग मुद्दे उठाना है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अली-बजरंग बली, प्रज्ञा ठाकुर, राजीव गांधी का भ्रष्टाचार। भाजपा का चुनाव प्रचार इस बार राष्ट्रीयता, आतंकवाद और मजबूत नेता तक सिमट गया है जो पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों एवं युवाओं की चिंता एवं आकांक्षाओं को संबोधित एवं समायोजित करने में विफल रहा है। भाजपा को निर्णायक चुनौती उत्तर प्रदेश में मिल रही है। अखिलेश एवं मायावती ने दलितों, मुस्लिमों एवं अधिकांश पिछड़ी जातियों के मजबूत गठबंधन का विकल्प देकर सत्ता में हिस्सेदारी का विश्वास दिलाया है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इस चुनाव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष भाजपा एव विपक्षी गठबंधन के पक्ष-विपक्ष में हुआ समाज का स्पष्ट क्षैतिज विभाजन है। इस विभाजन में जहां मुस्लिम, दलित एवं अधिकांश पिछड़ी जातियां गठबंधन के पक्ष में हैं वहीं सवर्ण और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा के पक्ष में हैं। कभी चुनावी परिणाम प्रभावित करने वाला निर्णायक 'फ्लोटिंग वोटर' इस चुनाव में गायब है। अभी तक हुए चुनावों पर मीडिया रपटों, भाजपा महासचिव राम माधव एवं शिवसेना के नेता संजय राउत के बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि संभवतः भाजपा बहुमत के आंकड़े तक नही पहुंच पाएगी। कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी भी बहुमत से दूर ही रहेगी।

ऐसे में संभावना है कि आगामी सरकार के स्वरूप एवं गठन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। इसे देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयासों में जुट गए हैं। संभावित स्थिति पर भाजपा की भी पैनी नजर है। इसकी पुष्टि कांग्रेस द्वारा सपा-बसपा प्रत्याशियों के चुनावों में रणनीतिक समर्थन में भेदभाव वाले बयान से होती है। क्षेत्रीय दलों के चुनाव पूर्व हुए गठबंधनों के कारण तीसरे मोर्चे के गठन में भी उलझनें हैं। जेडीएस कर्नाटक में कांग्रेस समर्थन से सरकार चला रहा है। बिहार में राजद कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। द्रमुक तमिलनाडु में न केवल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहा है, बल्कि उसके नेता स्टालिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर चुके हैं। जहां माकपा और कांग्रेस साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन केरल और बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में भाजपा एवं कांग्रेस से समान दूरी रखने वाले अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक एवं जगनमोहन रेड्डी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। क्षेत्रीय दलों में तालमेल बैठाने के लिए चुनाव परिणामों से दो दिन पहले 22 क्षेत्रीय दलों की बैठक के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सभी संभावनाओं के बीच यह तय है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व बढ़ने वाला है। अधिकांश क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपेक्षा क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर तीसरे मोर्चे की सरकार को प्राथमिकता देना पंसद करेंगे।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहंकार

मनुष्य जब कोई सफलता अर्जित करता है तो उसे अपनी क्षमता मान लेता है। वह अहंकार से भर उठता है कि कोई उसके समतुल्य नहीं है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो मनुष्य की हर सफलता परिस्थितिजन्य होती है। जब मनुष्य का तन और मन समन्वित होकर कोई कार्य करता है तो एक संकल्प का निर्माण होता है। संकल्प एक शक्ति मंडल है जो विघ्न बाधाओं को ध्वस्त करता चलता है और अनुकूल ऊर्जा संप्रेषित करता है। इसके प्रभाव में कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जब मन में दुविधा हो तो कितने भी प्रयास कर लें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि या तो संकल्प का अभाव होता है या संकल्प निर्बल होता है।

ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है और उनमें शक्तियां समाहित कर दी हैं। इन शक्तियों को प्रकट और कार्यशील करने का कार्य मनुष्य का है। हालांकि जब ईश्वर कृपा करता है तभी यह संभव हो पाता है। हर कोई वैज्ञानिक, साहित्यकार, चिकित्सक, राजपुरुष अथवा धर्मपुरुष नहीं बन जाता। हर किसी के पास धन, वीरता, नीति कुशलता नहीं है। कभी इसे संयोग, कभी प्रारब्ध और कभी पूर्वजन्म के कर्मों का फल भी मान लिया जाता है। कुछ भी हो, किंतु यह मन और तन के सुयोग बिना संभव नहीं है। ईश्वर किस पर कब और क्यों दयालु है, यह जान पाना मनुष्य के वश में नहीं है। कभी वह किसी साधु, संत के माध्यम से कृपा कर रहा है, कभी मन को एक निश्चित दिशा में प्रेरित कर सफलता के निकट ले जा रहा है।

विश्व में अधिकांश सफल लोगों ने यह स्वीकार किया कि अपनी सफलता से वे स्वयं चकित थे। यही सफलता और यश प्रतिष्ठा के बाद भी उनके अंदर विनम्रता बने रहने का मुख्य कारण था। जब कोई इस सच को मानने से इन्कार कर दे तो उसे अहंकारी होते देर नहीं लगती। यह परमात्मा की कृपा को नकारना और उससे दूर जाना है। अहंकार बड़े-बड़ों के विनाश का कारण बना है। रावण ने सोने का नगर बसाया था और बड़ा परिवार बनाया। सब कुछ जाता रहा। कौरव सौ थे, किंतु पांच पांडवों से पराजित हो गए। यह मनुष्य के हाथ में है कि वह क्या चुनता है। यदि उसने अहंकार चुना है तो इसका अर्थ है कि उसने विनाश चुना है जिसे टाला जाना असंभव है। अहंकार की ग्रंथि को दूर करके ही सफलता को निकट लाया जा सकता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

गणित की 'देवी' शकुंतला

ायोपिक्स का दौर है और ताजा घोषणा हुई है क विद्या बालन जल्दी ही महान गणितज्ञ और योतिषि शकुंतला देवी की बायोपिक में नजर आने वाली हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए विद्या ालन को भूल जाइए और फिर देखिए कि ाकुंतला देवी खुद आपको अपने टैलेंट से कतना रोमांचित कर देती हैं। गणित एक ऐसा वषय है जिससे बच्चे हमेशा अपनी जान छुड़ाना ाहते हैं, लेकिन इस कठिन विषय से शकुंतला ेवी की गहरी दोस्ती थी। इतनी कि वह बड़े से ड़े और कठिन से कठिन सवालों का हल मिनटों ों नहीं सेकेंडों में दे देती थीं।

शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर, 1929 में ेंगलुरु के एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ ा। उनके गुण का पता सबसे पहले उनके पिता ो लगा जब वह मात्र तीन साल की थीं। पिता ार्कस में काम करते थे और तब शकुंतला देवी ो एक ट्रिक सिखाते समय उन्हें पता चला कि नकी बेटी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। ाढ़े तीन साल की उम्र से शकुंतला देवी ने अपनी ्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और छह साल की उम्र में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय ों अंकगणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। फर 1944 में वह अपने पिता के साथ लंदन चली गईं। उन्होंने दुनिया के लगभग हर देश में इस तरह के शो किए जहां लोगों को अपने गणितीय गुणों को दिखाकर हैरान किया। यूं तो उन्होंने कई असंभव सवालों को हल किया है, लेकिन हम जैसे सामान्य लोग उनकी प्रतिभा का आकलन इस बात से कर सकते हैं कि हमें दो अंकों वाली दो संख्याओं को गुणा करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन 1980 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में शकुंतला देवी ने 13 अंकों की दो संख्याओं 7,686,369,774,870 और 2,465,099,745,779 को आपस में गुणा किया और मात्र 28 सेकेंड में उत्तर दे दिया 18,947,668,177,995,426,462,773,730। इस घटना को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

फिर से

अमूमन छात्र गणित से घबराते हैं लेकिन शकुंतला देवी की बात अलग थी। उनकी कहानी छात्रों को वास्तव में बहुत प्रेरित करेगी

1977 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में शकुंतला देवी का मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर 'यूनीवैक' से हुआ था। उनको गणना करके 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। इस सवाल को हल करने में शकुंतला को केवल 50 सेकेंड लगे थे। वहीं इसे हल करने में 'यूनीवैक' ने 62 सेकेंड का समय लिया था। इस घटना के बाद से ही उनको मानव कंप्यूटर का नाम दिया गया था। गणित के बारे में शकुंतला देवी का कहती थीं कि गणित सिर्फ गुणा भाग नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। वह कहती थीं कि मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इंसान ही तो हैं जिन्होंने कंप्यूटर बनाए, कंप्यूटर ने इंसान नहीं बनाए।

अंकों को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली शकुंतला देवी 2013 में 83 साल की उम्र

और भारत को फख्र है कि वह इस देश की थीं।

मेलबाक्स

चिंता उचित

नौकरशाही के भ्रष्टाचार की अनदेखी शीर्षक से लिखे अपने लेख में शिवदान सिंह ने देश में नौकरशाही को भ्रष्टाचार की ीमारी से बचाने के कुछ उपाय सुझाए हैं। हमारे देश की शासन यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साफ-सुथरी और वाबदेह नौकरशाही बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश ंत्रियों को प्रशासनिक कामकाज का उचित ज्ञान नहीं होता। ोकिन भारत में एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हां जिसके पास सत्ता होती है, सभी उसकी हां में हां मिलाते हैं। ौकरशाही भी चुनी हुई सरकारों के अधीन होती है। यही कारण कि देश में नौकरशाही सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली न गई है। अगर कोई नौकरशाह ईमानदारी की राह पर चलना ी चाहता है तो उसे हर वक्त अपनी नौकरी खोने या डिमोशन ी चिंता सताती रहती है। अगर सरकारें नौकरशाहों को अपनी ंगुलियों पर नचाना छोड़ दें और भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल सनी शुरू कर दें तो देश में भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा। ाथ ही ईमानदार नौकरशाहों के साथ भी कभी बेईमानी नहीं हो ाकेगी। लेखक ने सही समय पर यह मुद्दा उठाया है। अभी देश ें आम चुनावों का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी दलों को देश ी नौकरशाही को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अपनी-अपनी णनीति पेश करनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

शिक्षा प्रणाली में खामियां

ाज शिक्षा प्रणाली में काफी खामियां हैं। इसमें बड़े बदलाव ी आवश्यकता है। हाल ही में 10वीं व 12वीं परीक्षा परिणामों ें छात्रों ने 500 में 499 तक अंक प्राप्त किए हैं। निस्संदेह ये ात्र बहुत परिश्रमी होंगे तथा इन्होंने बहुत ध्यान से परीक्षा दी होगी। किंतु ये इतने प्रतिभाशाली हों, यह जरूरी नहीं। वर्तमा शिक्षा प्रणाली में वस्तुपरक बहुविकल्पी या छोटे उत्तर वाले प्रश्न अधिक होते हैं। सही उत्तर पर पूरे अंक मिल जाते हैं, किंतु यह सही उत्तर हमेशा ज्ञान पर आधारित नहीं होते, अनुमानित भी हो सकते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज विद्यालय -महाविद्यालय डिग्रीधारियों के उत्पादन के कारखाने बन गए हैं। ये उत्पादित छात्र अच्छे अंक लेकर डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु किसी विषय के अधिकारी नहीं कहे जा सकते। सीए की परीक्षा में कुछ विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, किंतु ये सिर्फ तीस प्रतिशत तक होंगे। सत्तर प्रतिशत प्रश्न निबंधात्मक, विचारात्मक या विस्तृत वर्णन वाले होंगे। इससे प्रतिभा का सही मूल्यांकन होगा। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को भी ऐसा परिवर्तन करना चाहिए। साथ ही कुछ प्रश्न व्यावहारिक ज्ञान व कार्य कुशलता से संबंधित होने चाहिए। तभी विद्यार्थियों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सकेगा।।

विनोद चतुर्वेदी, लोनी रोड, दिल्ली

ईवीएम का महत्व

दैनिक जागरण के 8 मई के अंक में संपादकीय आलेख, ईवीएम विरोधी मोर्चा, में यह कहना कि पचास प्रतिशत वीवी पेट पर्चियों का मिलान करने के बारे में विपक्ष की याचिका को सुना ही नहीं जाना चाहिए था, सही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आज तक किसी भी मतदाता ने यह शिकायत नहीं की है कि उसने जो बटन दबाया पर्ची उसके विपरीत निकली। जब मतदाता संतुष्ट है तो विपक्ष क्यों बवाल काट रहा है? ईवीएम के आने के बाद मतदाता का अधिकार सुरक्षित हुआ है और नतीजे भी शीघ्र मिलने लगे हैं। क्या विपक्ष अब भी बैलट पेपर से चुनाव के मोहपाश में जकड़ा है जब कमजोर तबके के लोग तक भी नहीं पहुंच के वोट भुगता दिए जात हमारा देश विश्व क ोकतंत्र है इसकी गरिमा बनाए रखने का दायित लों पर भी है।

णजीत वर्मा फरीदाबाद

अन्न की बर्बादी

देश में रोज कई सामा ोते हैं। इन कार्यक्रमों म मेहम क भोजन के कार्यक्रम म कई ें, जो कूड़ा-करकट म जाक में लाखों लोग आज भी भोज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंत व्यक ेे भोजन बनता है, उस अन् महीने लगते हैं, बल्कि काफ लेकिन हम चंद मिनट में इस अतः खाने के काय में उ ाथ ही अपने बच्च भी भ

hemahariupadhyay@gmail.com

इ द क भ

mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक ेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800 E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन